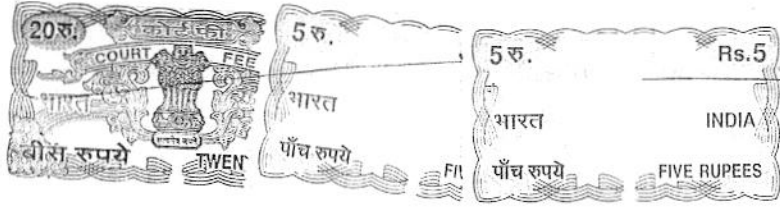


66



ता. - 1409-1-16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला-श्यापुर

परमजीत सिंह पुत्र श्री तारा सिंह जाट सिख,
निवासी - ग्राम मयापुरा, तहसील व जिला
श्यापुर (म.प्र.) -- आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा - कलेक्टर,
जिला- श्यापुर (म.प्र.) -- अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला श्यापुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/2010-11
स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.09.2011 के विरुद्ध
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु
प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

- 1- यहकि, तहसीलदार तहसील श्यापुर ने प्रकरण क्रमांक 20/2000-01/अ-86 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2001 से ग्राम मयापुर की भूमि सर्वे नं. 192/2 रकवा 12 बीघा 10 विस्वा पर आवेदक परमजीत सिंह पुत्र तारा सिंह जाट सिख निवासी मयापुर की भूमि आवंटित की गयी थी। उक्त प्रकरण में तहसीलदार श्यापुर द्वारा विधान सभा प्रश्न क्रमांक 2523 के अनुक्रम में आवंटित की गयी प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में बताया गया कि उक्त भूमि पूर्व में मोहम्मद पुत्र बसीर खॉं मुसलमान निवासी श्यापुर भूमि स्वामी के रूप में सम्बत् 2057 दर्ज है सम्बत् 2058 के खसरे में अपर कलेक्टर श्यापुर के प्रकरण क्रमांक 110/2000-01/बी-121 आदेश दिनांक 06.07.2001 द्वारा 12 बीघा 10 विस्वा भूमि का पट्टा आवेदक का निरस्त किया जाकर भूमि शासन में वेष्टित की गयी भूमि भूदान की है भूदान का पट्टा अधिनियम के तहत दिया जाता है। भूदान पट्टा देने की शर्ता का पालन नहीं किया गया इस्तहार विधिवत् नहीं है तामीली भूत्य के हस्ताक्षर नहीं है सर्वे नं. 152/2 का रकवा 5.262 है0 मोहम्मद पुत्र बसीर मुसलमान के नाम था जिसमें से केवल 12 बीघा 10 विस्वा का पट्टा निरस्त किया गया पट्टा दिनांक 06.07.2001 को निरस्त किया गया पुनः पट्टा दिनांक 05.09.2001 को दिया गया उक्त प्रकरण में म.प्र. भू-राजस्व

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/403-एक/16 जिला-शबोपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमात्रों आदि के हस्ताक्षर
14-2-19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री डी० एस० चौहान उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला शबोपुर के प्रकरण क्रमांक 19/2010-11/स्व० निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.9.2016 के विरुद्ध म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 15/4/19</p> <p><u>अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना</u></p>	